आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 07.03.2026
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा– पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई।

- भारतीय न्याय संहिता सहित नए आपराधिक कानूनों और अंतर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला।

- चम्पावत जिले के किसान कीवी उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण लेने के लिये तीन दिवसीय बागेश्वर भ्रमण पर।

शिलान्यास एवं लोकार्पण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संघर्ष के दौर से आगे बढ़कर विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए और हरिद्वार में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीमांत गांवों के विकास और पलायन रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। श्री शाह ने जोर देते हुए कहा कि देश में अतिक्रमण और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ मतदाता सूची, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस आरक्षी पद पर चयनित एक हजार 900 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अब पारदर्शी है और युवाओं को भी निष्पक्ष अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है तथा सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किसानों और महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़े हैं।
श्री धामी ने बताया कि चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई, पिछले वर्ष जीएसडीपी में 7 दशमलव दो–तीन प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में तीन लाख छप्पन हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये के समझौते धरातल पर उतारे जा चुके हैं।

उपलब्धि

भारत सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में चम्पावत जिले ने लगातार सातवीं बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जनवरी माह की रैंकिंग में जिले ने 123 में से 122 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि दर्ज की। एक रिपोर्ट–

चम्पावत ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इस वर्ष जनवरी में भी शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 40 रैंकिंग मदों में से जिले को 39 में 'ए' और एक में 'बी' श्रेणी मिली, जबकि 'सी' और 'डी' श्रेणी में कोई मद नहीं रहा। कुल 99 दशमलव एक–नौ प्रतिशत अंकों के साथ चम्पावत पहले स्थान पर रहा। बागेश्वर दूसरे और उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर रहे।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि लक्ष्य केवल शीर्ष स्थान पाना नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने विभागों को उत्कृष्टता बनाए रखने और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति को मजबूत करने के निर्देश दिए।

प्रथम स्थान

भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। अंतर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, आई०सी०जे०एस 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में राज्य ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार यह सफलता तकनीक आधारित न्याय प्रणाली के संकल्प का परिणाम है। रैंकिंग में हरियाणा दूसरे, असम तीसरे, सिक्किम चौथे और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर रहे। एक रिपोर्ट–

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नए कानूनों– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए मिशन मोड में काम किया गया। शीर्ष स्तर से ज़िला स्तर तक नियमित समीक्षा के कारण तकनीकी बाधाएं दूर की गईं और पुलिस विभाग नए कानूनी ढांचे के अनुरूप कार्य करने में सफल रहा।

आईसीजेएस 2.0 के तहत 'वन डेटा, वन एंट्री' प्रणाली लागू की गई, जिससे पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक विभागों के बीच डेटा का निर्बाध आदान–प्रदान सुनिश्चित हुआ। इससे कागजी प्रक्रिया कम हुई और मामलों के निस्तारण में तेजी आई। ई–साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित संग्रहण भी अनिवार्य किया गया है।

प्रदेश के 23 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी सुदृढ़ीकरण के तहत वर्चुअल सुनवाई और फॉरेंसिक मोबाइल वैन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई।

कीवी प्रशिक्षण

चम्पावत जिले के किसानों का एक दल कीवी उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण लेने के लिये बागेश्वर के शामा क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। उद्यान विभाग चम्पावत द्वारा कीवी मिशन के तहत जिले के 20 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

7 से 9 मार्च तक आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को कीवी की पौधरोपण तकनीक, रूट कटिंग, पोषण प्रबंधन और वैज्ञानिक पद्धतियों की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।

जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान किसानों को रोपण, वैज्ञानिक छंटाई, पोषण प्रबंधन और रोग नियंत्रण की बारीकियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाएगा।

कॉफी टेबल बुक विमोचन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन, देहरादून में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की कॉफी टेबल बुक 'समिट्सः द जर्नी ऑफ उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक' का विमोचन किया।

कॉफी टेबल बुक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विरासत से लेकर उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के गठन, बैंक के विकास, वित्तीय समावेशन, तकनीकी नवाचार, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के सशक्तीकरण सहित प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की दृष्टि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है और इस दिशा में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में अहम योगदान दिया है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकाशन को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि बैंक की भूमिका और योगदान की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे।